प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 46 अंक–34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 30–06 सितम्बर 2021 मूल्य पांच रूपए

टीकाकरण में पहले स्थान पर और कोविड के नाम पर ही टाले गये उपचुनाव

अनुराग की यात्रा में मिला जन समर्थन भी चुनाव का साहस नहीं दे पाया

⇨ क्या उपचुनाव टालने के बाद स्वर्ण जयन्ती समारोहों का आयोजन हो पायेगा

⇨ क्या मुख्यमन्त्री और मन्त्री राजनीतिक रैलियां जारी रख पायेंगे

⇨ क्या इस दौरान की गई करोडों की घोषणायें अभी अमली शक्ल ले पायेंगी

⇨ क्या उपचुनावों से भागना सरकार की राजनीतिक मजबूरी है

शिमला/शैल। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उपचुनावों की तारीखें घोषित करते हुए अन्य राज्यों की 32 विधानसभा सीटों और तीन लोकसभा सीटों के लिये उपचुनाव अभी टाल दिये हैं। इसमें हिमाचल में होने वाले चारों उपचुनाव भी टल गये हैं। चुनाव आयोग ने यह फैसला संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ पहली सितम्बर को हुई बातचीत में दिये गये फीड बैक के आधार पर लिया है। इसमें कोविड, बाढ़ और त्यौहारों को लेकर स्थिति की रिपोर्ट लिखित में लेने के बाद चुनाव टाले गये हैं। बंगाल और उड़ीसा में 30 सितम्बर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 अक्तूबर को होगी। हिमाचल की ओर से फीडबैक मुख्यसचिव, स्वास्थ्य सचिव और डी जी पी की ओर से दिया गया है।

प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में इस फैसले को सरकार का उपचुनावों से भागना करार दिया जा रहा है। क्योंकि कोविड के टीकाकरण में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर होना एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिये प्रदेश के छः लोगों का प्रधानमन्त्री के साथ वैक्सीन संवाद करवाया जा रहा है। इस संवाद के लिये अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से खूब प्रचार किया गया है। पूरे प्रदेश में एल ई डी स्क्रीन के माध्यम से लाईव दिखाने का प्रबन्ध किया गया है। जब कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी उपलब्धि है तब कोविड के कारण उपचुनावों को टाला जाना सारे दावों पर ही सवाल खड़ा कर देता है। फिर कोविड के मामलों और उससे हो रही मौतों के जो आंकड़े कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं उनसे स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि पर सन्देह का कोई कारण नहीं रह जाता है। इसी तरह अब बरसात लगातार कम होती जा रही है और बाढ़ का भी कोई बड़ा नहीं है। आने वाले त्यौहार भी 3 अक्तूबर के बाद ही आने वाले हैं। इसलिये इन आधारों पर चुनावों का टाला जाना बहुत ज्यादा संगत नहीं लगता है। क्योंकि यह सामान्य धारणा है कि शीर्ष अफसरशाही राजनीतिक आकाओं के आगे 'इन्कार' कहने करने का साहस नहीं कर पाती है। इसलिये इन आधारों पर चुनाव टालने का फैसला शुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है।

इसलिये राजनीतिक कारणों पर भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इतने लम्बे समय के लिये लोकसभा और विधानसभा में इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व न हो पाना लोकतन्त्र की स्थापनों पर ही कई सवाल खड़े कर जाता है। इस समय कोविड से भी ज्यादा गंभीर चर्चा का विषय विवादित कृषि कानून बन चुके हैं। हिमाचल में चल रहे सेब सीजन ने प्रदेश के एक बड़े हिस्से में इन कानूनों के व्यवहारिक पक्ष के कारण जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस तरह अदानी के ऐग्रो फ्रैश के कारण सेब की कीमतें घटी हैं उससे बागवान को यह समझ आ गया है कि जब तक यह विवादित कानून रहेंगे तब तक प्रतिवर्ष उसके साथ ऐसा ही घटेगा। इस मुद्दे पर बागवानी मन्त्री, भाजपा के प्रदेश प्रभारी और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने जिस तरह से अदानी का पक्ष लिया उससे यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के सत्ता में रहते इन कानूनों की वापसी सम्भव नहीं है। इसी कारण से किसान आन्दोलन के राष्ट्रीय नेताओं ने इन उपचुनावों के लिये ''भाजपा को वोट नहीं'' अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया था। इसी ऐलान का प्रभाव था सोलन के आड़ती द्वारा अपना ब्यान वापिस लेना और ठियोग में बागवानी मन्त्री महेन्द्र सिंह का घेराव होना। इसलिये यह उपचुनाव टालने के लिये इस मुद्दे की प्रभावी भूमिका रही है।

इसी के साथ भाजपा की अन्दरूनी स्थिति पर नजर दौड़ायें तो यह सामने आता है कि पिछले दिनों लाहौल स्पिति से मन्त्री डा. रामलाल मारकण्डे के साथ जन जाति मोर्चा के लोगों का उलझना, कुल्लु में पूर्व मन्त्री महेश्वर सिंह के तेवर और पंडित खीमी राम का अभी से चुनाव लड़ने का दावा करना मण्डी में अनिल शर्मा की बगावत और महेन्द्र सिंह का लगातार विवादित होते जाना संगठन के भीतर की स्थिति पर काफी रोशनी डालता है। शिमला में सुरेश भारद्वाज और स्व नरेन्द्र बरागटा के बीच रही रिश्तों की तल्खी अपरोक्ष में इस उपचुनाव में भी मुखर होने लग पड़ी थी। इसी तल्खी का प्रमाण है कि जुब्बल कोटखाई में दो उपमण्डल कार्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमन्त्री को करनी पड़ी। इसी के कारण मुख्यमन्त्री को प्रदेश के अन्य भागों मे जहां –जहां भी वह गये वहीं पर घोषणाओं के अंबार लगाने पड़े हैं। चौथे वर्ष में नेताओं के एक बड़े वर्ग को ताजपोशीयों के तोहफे देने पड़े है। अब जब चुनाव टल गये हैं तब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरान की गयी घोषणाओं को कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाता है और इसके लिये कितना कर्ज लिया जाता है। ऐसे में कुल मिलाकर यदि निष्पक्षता से आकलन किया जाये तो यही सामने आता है कि इतनी सारी उपलब्धियों के आकड़ों के बावजूद उपचुनावों में जीत को लेकर जब सरकार और संगठन आश्वस्त नही हो पाये तब चुनावों को टालने का फैसला लिया गया। अब यह फैसला लेने के बाद क्या सरकार स्वर्ण जयन्ती समाराहों का आयोजन कर पायेगी? क्या अब रथयात्रा निकल पायेगी? क्या मुख्यमन्त्री और अन्य मन्त्री जनता में जाकर राजनीतिक रैलीयों का आयोजन कर पायेंगे। क्योंकि जब कोविड के कारण चुनाव टाले गये हैं तब उसी कोविड के चलते रानजनीतिक आयोजन कैसे हो पायेंगे आने वाले समय में यह एक बड़ा सवाल होगा।

इसी संद्धर्भ में यह सवाल भी उठना शुरु हो गया है कि अभी अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा में जो जन समर्थन मिला है उससे भी सरकार उपचुनावों में जाने का साहस क्यों नहीं जुटा पायी। स्मरणीय है कि इस यात्रा के बाद भाजपा की ओर से जो ब्यान जारी किया गया है उसमें दावा किया गया है कि यात्रा के लिये 184 स्थानों पर आयोजन रखे गये थे और इनमें करीब एक लाख दो हज़ार लोग शामिल हुए हैं। गणना का यह आंकडा भाजपा की ओर से ही आया है। उसी ने यह गिनती जारी की है और इसके मुताबिक प्रत्येक आयोजन में करीब 500–550 लोगों का शामिल होना सामने आता है। यदि इस आंकडे का विश्लेषण किया जाये तो यही सामने आता है कि यात्रा के दौरान मिलने वालों में मण्डल और जिला कार्यकारिणीयों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त आम आदमी बहुत कम रहा है। वैसे तो विश्लेष्कों की नज़र में इस तरह के आयोजनों में आने वालों की गिनती कर पाना संभव ही नहीं हो पाता है। फिर यदि इस तरह की गिनती कर भी ली गई हो तो उसके आंकडे ऐसे सार्वजनिक नहीं किये जाते। क्योंकि पांच दिनों में 630 किलो मीटर की लम्बी यात्रा में सबसे बड़ी पार्टी और प्रधानमन्त्री का विश्वभर में लोकप्रियता में पहले स्थान पर होने का दावा करने वाली पार्टी के इतने आयोजनों में इतने ही लोगों का आ पाना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह आंकडे जारी करके अनुराग को मिले समर्थन की धार को कुन्द करने का प्रयास है। स्वभाविक है कि जिस पार्टी के अन्दर ऐसे आयोजनों में शामिल होने वालों की इस तरह गिनती की जा रही हो वह चुनाव के लिये कितनी तैयार होगी।

शिक्षक दिवस पर राज्यपाल ने किया 18 शिक्षकों को सम्मानित

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पीटरहॉफ शिमला में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वर्ष 2021 के लिए 17 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार और एक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एस राधाकृष्णन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका जन्म दिवस देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति, शिक्षाविद् और सफल प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि उनके विचार भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे और उन्हें विश्वास था कि भारतीय परम्परा से जुड़ी शिक्षा देश में फिर से लागू होगी।

आर्लेकर ने कहा कि समाज में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है और शिक्षक समाज का निर्माण और मार्गदर्शन करते हैं इसलिए शिक्षकों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में गुरू को भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि गुरू के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। गुरू और शिक्षक के रिश्ते में निरंतरता होती है और इस दृष्टि से शिक्षक की भूमिका मार्ग दर्शक के रूप में और अधिक बढ़ जाती है। शिक्षक भावी पीढ़ी के निर्माण के साथ एक आदर्श स्थापित करते हैं।

राज्यपाल ने चरित्र, व्यक्तिगत एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों में कमी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि इन कारणों से देश कई क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया का आधार है। बच्चों के समग्र विकास का उद्देश्य मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है इसलिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करें।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा एक महान व्यवसाय है और यह एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि विद्यार्थी शिक्षकों के आचरण, चरित्र और विचारों से प्रभावित होते हैं। शिक्षकों को ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए।

पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने शिक्षण समुदाय से और अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण भाव से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी शिक्षा प्रणाली की उपनिवेश प्रणाली से स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा नीति के लिए जितना संभव हो उतना योगदान देना चाहिए। इस दिशा में हमें योगदान देना चाहिए जो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने स्मारिका का विमोचन भी किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11,23,283 विद्यार्थी हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में 79,234 शिक्षक और 17,934 गैर-शिक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2018 से प्रदेश के 4,838 शिक्षकों की सेवाएं नियमित की गई हैं जो अपने आप में एक इतिहास है। उच्चतर शिक्षा में 537 सहायक प्राध्यापक, 2,475 प्रवक्ता, 334 डीईपी, 466 लिपिक और 791 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया गया है।

उन्होंने कहा कि 5,814 पद उन लोगों द्वारा भरे गए हैं जो वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2018 से प्रदेश सरकार ने 8,136 अध्यापकों की नियुक्ति की है जबकि 5,095 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 4000 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही हैं जिसके लिए विभागीय स्तर की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

18 सितम्बर को रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी अस्पताल शाखा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि 18 सितम्बर, 2021 को रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा रेडक्रॉस भवन शिमला में सदस्यों के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यशाला आयोजित की जाएगी ताकि भविष्य में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को जागरूक किया जा सके।

डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी ने वर्ष 2021 में 61 रक्तदान शिविरों के आयोजन करवाए। प्रदेश में 3416 पल्स ऑक्सीमीटर, 87885 फेस मास्क, 9486 पीपीई किट, 9522 फेस शील्ड तथा 40,710 दस्ताने वितरित किए। इस दौरान 7087 राशन किट भी प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 1942 लोगों को चिकित्सा परामर्श तथा 3657 लोगों को मानसिक-सामाजिक सहायता प्रदान की गई। डॉ. साधना ठाकुर ने कहा कि प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए पेड़-पौधों से नवाजा है। इसलिए रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रदेश में स्वयंसेवियों की भागीदारी से पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1.10 लाख पौधें रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के तहत 65000 पौधें रोपित किए जा चुके हैं, जिनमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं।

बैठक के दौरान डॉ. साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा की नई कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए मधु सूद को उपाध्यक्ष, डॉ. किम्मी सूद को अवैतनिक सचिव, बिमला कश्यप, सुषमा मिनोचा व निरता आकरे को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नामित किया। इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा सचिव पी.एस. राणा ने डॉ. साधना ठाकुर का स्वागत किया तथा उन्हें बैठक से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी अस्पताल कल्याण शाखा के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

एसजेवीएनएल अध्यक्ष ने दी राज्यपाल को विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं जानकारी

शिमला/शैल। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की और उन्हें भारत और विदेशों में एसजेवीएनएल की विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी।

शर्मा ने कहा कि एसजेवीएनएल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में दो जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। जिसमें 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना और 210 मेगावाट लुहरी प्रथम चरण जल विद्युत परियोजना शामिल हैं।

इनके अलावा, एसजेवीएनएल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 9 और जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिनमें से 03 सतलुज बेसिन और 06 चिनाब बेसिन पर हैं। उन्होंने कहा कि एसजेवीएनएल लाहौल स्पीति जिले के काजा में 880 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का क्रियान्वयन भी कर रहा है।

सरकारी नीतियों को संवेदनशीलता से कार्यान्वित किया जाये:राज्यपपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा, पुनर्वास व चहुंमुखी एवं समग्र विकास के लिए सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों को अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि परिषद की आम सभा की बैठक नियमित तौर पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि रूपरेखा के साथ इस दिशा में प्रभावी पग उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि दोष वाले बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, उनका अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है।

इस अवसर पर राज्यपाल को वरिष्ठ अधिकारियों ने परिषद् की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

प्राकृतिक खेती में भूमि की उर्वरता बढ़ाने की क्षमता: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्राकृतिक खेती के परिणाम धरातल पर देखने को मिले हैं और इसका लाभ अब हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के किसानों को दिखाई दे रहा है और परिणामस्वरूप लगभग एक लाख 30 हजार किसान इस खेती से जुड़े हैं।

राज्यपाल यह बात राजभवन में प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई की बैठक में बोल रहे थे। आर्लेकर ने कहा कि वे किसान नहीं हैं, लेकिन वे इस कृषि प्रणाली को लंबे समय से बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सुभाष पालेकर से भी मुलाकात की थी और उनसे खेती के इस तरीके की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि इसे अपनाने से किसान साल भर एक ही समय में एक ही जमीन से अलग-अलग फसलें प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह वह पूरे वर्ष व्यस्त रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि देशी गाय की रक्षा के लिए भी यह कृषि पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। इस कृषि पद्धति में पहाड़ी गाय का महत्व समझाया गया है और इसे बढ़ावा देने से गायों का संरक्षण भी संभव होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भूमि जोत बहुत कम है और खेती की इस पद्धति को अपनाने से किसानों को अधिक उपज मिलेगी और लागत भी कम होगी। उन्होंने उनसे जनजाती क्षेत्रों में भी इस खेती को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान संदर्भ में, प्राकृतिक खेती में भूमि की उर्वरता बढ़ाने की क्षमता है और इस प्रकार उत्पादित उत्पाद स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होंगे।

इस अवसर पर कृषि सचिव अजय शर्मा ने राज्यपाल को प्राकृतिक खेती के अलावा किसानों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया।

प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने भी प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति और कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश्वर चंदेल ने योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

जूनियर मुकेबाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर स्नेहा नेगी को बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में 66 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने के लिए स्नेहा नेगी को बधाई दी। स्नेहा नेगी जिला किन्नौर के सांगला क्षेत्र की रहने वाली है, जिसने संयुक्त अरब अमीरात की मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के लोगों के लिए सम्मान की बात है, विशेषकर महिलाआं के लिए, जो हर क्षेत्र में अग्रणीय है तथा राष्ट्र के साथ-साथ राज्य का भी नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्नेहा नेगी ने यह उपलब्धि अपने परिश्रम और निष्ठा से प्राप्त की है। उन्होंने स्नेहा नेगी की उपलब्धि के लिए उसके प्रशिक्षक और अभिभावकों को भी बधाई दी।

HPPWD TENDERS

Sealed item rate tenders on forms 6 & 8 are hereby invited by the **Executive Engineer, Dharamshala Division, HP.PWD., Dharamshala** for the below mentioned works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD so as to reach in his office on or before **24.09.2021 upto 11:00 AM** and the same shall be opened on the same day **at 11:30 AM** in the presence of the tender opening committee and intending contractors/firms or their authorized representatives. The tender documents can be had from this office against cash payment/Non refundable) **up to 4:00 P.M. on 22.09.2021.**The applications for issue of tender forms shall be received **upto 1:00 P.M. on 21.09.2021.**

The Earnest Money in the shape of NSC's / FDR's Deposit/Bank Guarantee at Call of any of the Post office/Bank duly pledged in favour of XEN HPPWD., Dharamshala must be accompanied with the tender documents. Please note that no exemption orders of earnest money will be entertained. Conditional tenders and the tenders received without earnest money as mentioned above will summarily be rejected. The offer of the tenders shall be kept open for 90 days. The Executive Engineer reserves the right to reject any tender or all tenders without assigning any reasons. The contractors should be registered as a dealer under H.P. Sales Tax Act, 1962 and also produce the clearance certificate from the Excise and Taxation department. The tender documents shall only be issued to those contractors/firms who will produce the photo copy of their enlistment/renewal, if it happens to be a holiday on the day of opening of tenders the same will be opened on the next working day at the same time and venue:-

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost in Rs.	EMD	Time limit	Cost of Tender Form
1.	Construction of Road From BSNL telecom complex (near Circuit House) to Link with GCDM road near C.E. (K.Z) PWD residence KM 0/00 to 0/915 (Sanjay Marg Ward No.06) at Tehsil Dharamshala in Distt Kangra H.P (Deposit work Against Smart City). (Sub Head:- Providing & laying cement concrete pavement at RD 0/210 to 0/230 KM, steel work and construction of PCC Breast wall)	496908/-	10000/-	Three month	350/-
2.	Construction of Road From BSNL telecom complex (near Circuit House) to Link with GCDM road near C.E. (K.Z) PWD residence KM 0/00 to 0/915 (Sanjay Marg Ward No.06) at Tehsil Dharamshala in Distt Kangra H.P (Deposit work Against Smart City). (Sub Head:- Providing & laying HDPE pipe qwith inspection chamber at RD 0/074 to 0/120 KM)	264472/-	5300/-	Three month	350/-
3.	Annual repair and mainstenance of link road Dari to Darnu KM 0/000 to 2/040 in Tehsil Dharamshala in Distt Kangra H.P (SH:- Construction of Retaining wall at RD 2/615 to 2/648)	250206/-	5000/-	Two month	350/-

Adv. No. 3813/21-22 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह नौवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष तथा लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठयक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा सम्बन्धी मुददों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में सम्बन्धित नीति का अध्ययन करेगी।

बैठक में जिला चम्बा की ग्राम पंचायत बाट के आधार गांव में पशु औषधालय खोलने के साथ औषधालय के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति मण्डल शाहपुर के अन्तर्गत रानीताल में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल और इस उप-मण्डल के तहत ठाकुर द्वारा में नया अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जल शक्ति उप-मण्डल उदयपुर के अन्तर्गत पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा के लिए जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के सुन्दरनगर विधानसभा क्षेत्र के चनोल में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला सिरमौर के राजगढ़ में नया स्वास्थ्य खंड कार्यालय खोलने के साथ आवश्यक पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई।

मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के नग्गर शिक्षा खण्ड में ग्राम पंचायत पिछलीधार के गलंग गांव में तथा शिक्षा खण्ड कुल्लू-2 में ग्राम पंचायत बस्तोरी के सराली गांव में नए राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र के ततवाली तथा ज्वाली क्षेत्र के नडोली में राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के शाहपुर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला करेरी खास को राजकीय उच्च पाठशाला तथा नगरोटा बगवां में राजकीय उच्च पाठशाला जलोट को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी।

बैठक में जिला बिलासपुर के सवारघाट क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला री खास को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के चम्बा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं जंघी, धामग्रां, ओयाल तथा ककला को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन करने व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धदोह, बस्सी, बखली तथा देवधार में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के झण्डूता क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंधीर में आवश्यक पदों के सृजन के साथ विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय तकीपुर में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला सोलन के दून क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला झाड़माजरी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मण्डी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक नवगठित नगर निगम में कनिष्ठ अभियंता के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद भरने का निर्णय लिया गया। इन पदों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी जब तक इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता।

बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ मण्डी जिले के थलौट में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल सृजित करने का निर्णय लिया।

जिला सिरमौर के टिम्बी में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने के साथ इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने विकास खंड नगरोटा बगवां और कांगड़ा के क्षेत्र से अलग कर बरोह में नया विकास खंड गठित करने को भी स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने विकास खंड बमसन की 6 ग्राम पंचायतों को विकास खण्ड हमीरपुर में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा मिल सकें।

13 से 20 सितम्बर तक होंगी विभागीय परीक्षाएं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सभी श्रेणीयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय परीक्षाएं 13 से 20 सितंबर, 2021 तक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजौली, शिमला में आयोजित की जाएंगी।

प्रवक्ता ने बताया कि 13 सितंबर, 2021 को पेपर-1 अर्थात् वित्तीय प्रशासन के आयोजन की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक (बालिका) विद्यालय मण्डी में भी की गयी है।

हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा सभी पात्र उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि रोल नंबर डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए वे अपने पीएमआईएस खातों की जांच करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बंधित उम्मीदवारों के रोल नंबर डाक द्वारा भेजे गए हैं और वे अपने रोल नंबर हिपा (एचआईपीए) की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

उम्मीदवारों को केवल संदर्भ पुस्तकों, अधिनियम और विभागीय मैनुअल व पाठ्य पुस्तकों की अनुमति है और टेक्स्ट बुक, हेल्प बुक और गाइड की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और निर्देशों की अवहेलना को अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा।

उम्मीदवारों को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र या परीक्षा से 72 घंटे के भीतर जारी आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना आवश्यक है।

राज्य सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र ड्रग एंड क्राइम कार्यालय (यूएनओडीसी) की वैश्विक परियोजना जीएलओ स्मार्ट के तहत दो शोध प्रकाशनों, ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट 2020 तथा क्षेत्रीय अवलोकन: एशिया और ओशिनिया 2020 का हिंदी अनुवाद जारी किया। ग्लोबल स्मार्ट कार्यक्रम (यानि सिंथेटिक्स मॉनिटरिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड ट्रेंड्स) का उद्देश्य सदस्य राज्यों की क्षमता में सुधार, प्रबंधन, विश्लेषण, रिपोर्ट और अवैध सिंथेटिक दवाओं की जानकारी साझा करना है। कार्यक्रम का दक्षिण एशिया घटक पिछले वर्ष शुरू किया गया था।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे से लड़ने में सहायता करने के लिए यूएनओडीसी द्वारा किए गए सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य ने उनकी अध्यक्षता में नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है और नई ड्रग पॉलिसी भी तैयार की है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए यूएनओडीसी के सहयोग और भागीदारी की आशा करती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यूएनओडीसी द्वारा साझा की गई जानकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज का निर्माण करना प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवा पीढ़ी का कर्तव्य है।

इस अवसर पर यूएनओडीसी स्मार्ट कार्यक्रम के वैश्विक प्रमुख, मार्टिन राल्थेलहुबर, वियना से ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और स्मार्ट कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह दोनों प्रकाशन स्मार्ट द्वारा किए गए पहले हिन्दी अनुवाद हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के आग्रह पर तैयार किया गया है ताकि राज्य में इनकी व्यापक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यूएनओडीसी की ओर से नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में निरंतर सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

दक्षिण एशिया के लिए यूएनओडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के कानून प्रवर्तन विशेषज्ञ जयंत मिश्रा ने पिछले एक वर्ष के दौरान कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दिया।

हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए यूएनओडीसी का आभार व्यक्त किया।

मुख्य सचिव ने राज्य में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

शिमला/शैल। राज्य में शहरी गैस वितरण (सीजीडी), एथेनॉल संयंत्र और अन्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह बात मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान कही।

बैठक के दौरान जिला ऊना के जीतपुर बहेड़ी औद्योगिक क्षेत्र और सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) एवं मदर स्टेशन पर 125 केएलपीडी-1 जी एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने राज्य में सीजीडी, एथेनॉल संयंत्र और परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे समय पर पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राज्य में रेल फेड डिपो स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला ऊना में एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए जमीन की मंजूरी का मामला एकल खिड़की क्लीयरेंस बैठक में भेजा जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक गैस पाइप लाइन बिछाने के कार्य में तेजी ला निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए कहा।

बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड और भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

विवेकहीन व्यक्ति महान ऐश्वर्य पाने के बाद भी नष्ट हो जाते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या सोशल मीडिया बेलगाम है

क्या सोशल मीडिया के ट्वीटर, फेसबुक और यू ट्यूब जैसे मंच बेलगाम हो गये हैं? क्या वेब पोर्टलों पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया? क्या यह न्यूज़ पोर्टल कुछ भी न्यूज चला देते हैं और किसी के भी प्रति जवाब देह नहीं हैं? क्या ये सिर्फ बड़े प्रभावशाली लोगों की ही बात सुनते हैं? जजों और अन्य संस्थानों की भी बात नहीं सुनते हैं? यह सवाल और चिन्ताएं सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश ने निजामुदीन मरकज में तबलीगी समाज के हुए एक आयोजन के प्रकरण में जमीयेत-उलेमा-ए- हिन्द की ओर से आयी याचिका की सुनवाई के दौरान उठाये हैं। इन सवालों के बाद इस संबंध में एक बहस छिड़ गयी है। कुछ वेबसाईटों पर संचालकों ने इन आरोपों को नकारते हुए साफ कहा है कि इनके लिये नियामक प्रावधान हैं और उनके तहत इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायलय में इस पर सालीसीटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखते हुए यह बताया कि नये आई टी नियमों में इसका पूरा प्रावधान है लेकिन कई उच्च न्यायालयों में इन नियमों को चुनौती दी गयी है और एक उच्च न्यायालय ने तो अन्तरिम रोक लगा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय में इन सारी याचिकाओं को अपने पास लेकर इन पर सुनवाई करने और फैसला देने की गुहार लगाई गयी है और एक उच्च न्यायालय ने तो अन्तरिम रोक लगा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय में इन सारी याचिकाओं को अपने पास लेकर इन पर सुनवाई करने और फैसला देने की गुहार लगाई गयी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है तथा अगली तारीख भी तय कर दी गयी है। इसलिये इन सवालों पर अभी कोई राय बनाना सही नहीं होगा।

लेकिन प्रधान न्यायधीश की इन चिन्ताओं को हलके से नहीं लिया जा सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई मंच भी नही है जहां इन सवालों का कोई हल निकल सकता है। इसलिये इस संद्धर्भ में कुछ और सवाल तथा तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना समय की मांग हो जाता है। तबलीगी समाज का जब यह सम्मलेन हुआ उससे पहले देश में नागरिकता कानून के विरोध में दिसम्बर 2019 से ही आन्दोल शुरू हो चुका था। 15 दिसम्बर से शाहीनबाग आन्दोलन स्थल बन चुका था। आन्दोलन का विरोध करने वाले और आन्दोलन के समर्थक एकदम आमने सामने की स्थिति में आ गये थे। इस स्थिति का अन्तिम परिणाम 23 फरवरी से 29 फरवरी तक दिल्ली दंगों के रूप में सामने आया जिसमें 53 लोगों की जान चली गयी। इसमें मरने वालों में 17 हिन्दु थे दो की पहचान नहीं हो सकी और शेष सब मरने वाले मुस्लिम थे। उस आन्दोलन में किन बड़े नेताओं ने कैसे कैसे नारे लगाये हैं यह पूरा देश जानता है। इन नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिये कोई करवाई नहीं हुई है। यह भी सबके सामने है। दिल्ली दंगो के लिये जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिनके खिलाफ मामले बनाये गये आज उन मामलों की सुनवाई में दिल्ली पुलिस की कितनी फजी़हत हो रही है यह भी आज देश के सामने आता जा रहा है।

इसी सारे परिदृश्य के बाद जब 24 मार्च को कोरोना से बचाव के लिये पूरे देश में लॉकडाऊन लागू कर दिया गया। इसी दौरान तबलीगी समाज का निजामुदीन मरकज में सम्मेलन हो रहा था। लॉकडाऊन के कारण यातायात के सारे साधन एकदम बन्द हो गये। इसके कारण इस सम्मलेन में आये करीब बारह सौ लोग वहीं मरकज में बंध कर रह गये। इनमें से करीब चौदह लोग कोरोना संक्रमित हो गये। इनके संक्रमित होने से इन्हें ही कोरोना का कारण मान लिया गया। यह लोग मुस्लिम थे और विदेशों से लेकर देश के हर राज्य से आये हुए थे, इसलिये जब इनकी अपने-अपने यहां को वापसी हुई तब इन्हें कोरोना का कारण मानते हुए कोरोना बंब कह कर हर मीडिया ने प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसमें सोशल मीडिया के मंच ही नहीं वरन् प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया के भी मंच शामिल हो गये। पूरे कोरोना काल में किस तरह मीडिया के माध्यम से हिन्दु -मुस्लिम को बांटा गया यह किसी से छिपा नहीं है। इसमें सभी तरह का अधिकांश मीडिया बेलगाम हो गया था यह एक कड़वा सच है।

लेकिन कडवा सच यह है कि आज सभी राजनीतिक दलों ने अपने- अपने आईटी सैल खोल रखे हैं। इनके माध्यम से अपने विरोधीयों के खिलाफ प्रचार करने के लिये दर्जनों वैबन्यूज पोर्टल इन दलों ने खोल रखे हैं। इनके माध्यम से बड़े- बड़े नेताओं और अन्य लोगों का चरित्र हनन किया जा रहा है। इन्ही के माध्यम से हिन्दु-मुस्लिम की दीवार खींची जा रही है जो पूरे देश के लिये घातक सिद्ध होती जा रही है। इसलिये सोशल मीडिया के मंचों पर नियन्त्रण रखने के लिये राजनीतिक दलों के आई टी सैलों पर भी नज़र रचाना बहुत ज़रूरी है। इस संद्धर्भ में राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिये एक अलग से सहिंता रहनी चाहिये। क्योंकि जिस तरह से एक धारा विशेष के लोग हिन्दु-मुस्लिम फैलाते जा रहे हैं उसके परिणाम हरेक के लिये घातक होंगे। क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से हिन्दु और मुस्लिम हिन्दु और मुस्लिम में दरार पैदा की जा रही है। इसमें जब तक भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को दण्डित नहीं किया जायेगा तब तक कोई भी मंच बेलगाम ही रहेगा।

राज्य में जल जीवन मिशन को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर रही है सरकार

15 हजार 256 फुट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग गांव में राज्य सरकार ने पहुंचाया नल से जल

शिमला। प्रदेश के हर परिवार को उसके घर पर आसानी से पेयजल मिले और लोगों को पानी के लिए परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए राज्य सरकार के प्रयास अब जल जीवन मिशन के तहत फलीभूत होने लगे हैं। मिशन के अन्तर्गत जिला लाहौल- स्पीति में 15 हजार 256 फुट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग गांव के घर-घर में भी राज्य सरकार ने नल से जल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है।

कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कर रही है। हर घर, नल से पेयजल पहुंचाने की राज्य सरकार की योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते यह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में देशभर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर है।

प्रदेश में लगभग 17 लाख घरों में नल लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक 14 लाख 50 हजार घरों में नल उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद लगभग 18 माह की छोटी-सी अवधि में राज्य में 6 लाख 5 हजार नल लगाए गए हैं। हर घर, नल से पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके दृष्टिगत विभाग कार्य योजना तैयार कर उसे अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है।

वर्ष 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य को जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए 2260 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई है, जिसमें से जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर अब तक 1107 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की परफॉरमेंस के आधार पर राज्य को 283 करोड़ का इंसेन्टिव भी प्राप्त हुआ है जो प्रदेश के कर्मचारियों विशेष कर जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों के लिए भी गर्व की बात है। प्रदेश को मिला यह इंसेन्टिव जल शक्ति विभाग की बेहतर नीतियों व कार्य प्रबन्धन के साथ-साथ कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बदौलत ही मिल पाया है।

राज्य में जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से पानी उपलब्ध करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। राज्य में विभिन्न पेयजल योजनाओं में सुधार व अनेक नई योजनाओं को बना कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में 283 पेयजल योजनाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 1120.24 करोड़ रुपये की योजनाओं के प्राकलन (डीपीआर) तैयार किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर अब तक 288.11 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

राज्य में वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न योजनाओं के संवर्धन और सुधार के लिए 764 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 888 करोड़ रुपये की लागत की 107 परियोजनाएं और तैयार मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है।

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन की विभिन्न गतिविधियों के मामले में हिमाचल प्रदेश देशभर में शीर्ष स्थान पर है। मिशन के अन्तर्गत जिला लाहौल-स्पीति में 15 हजार 256 फुट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग गांव के घरों में भी नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मिशन की गतिविधियों को बिना किसी रूकावट के निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि 15 अगस्त, 2022 तक राज्य के हर घर में नल हो।

पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए समिति गठित

शिमला। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा और उनमें उपयुक्त बदलावों की सिफारिशें करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसार भारती के सदस्य अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंत्रालय के इस निर्णय को मीडिया के इको स्पेस में हुए कई बदलावों, जिसमें कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में पत्रकारों की मृत्यु हो गई थी और 'श्रमजीवी पत्रकार' की परिभाषा का व्यापक आधार होना शामिल है, के आलोक में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पत्रकार कल्याण योजना, जोकि पिछले कई वर्षों से अस्तित्व में है, को इस देश के पत्रकारों के हित में भविष्य की दृष्टि से लाभकारी बनाने और उसके कवरेज को व्यापक आधार देने की जरूरत है। ऑक्यूपेशनल, सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अधिनियमन के साथ पारंपरिक और डिजिटल मीडिया, दोनों, में काम करने वाले पत्रकारों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। इसके अलावा, इस योजना के तहत कल्याण और लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच संभावित समानता को भी जरूरी समझा गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल के दिनों में उन पत्रकारों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिनकी दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक मामलों में प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता दी गई है।

समिति द्वारा दो महीने के भीतर समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है। इसकी सिफारिशों से सरकार को पत्रकारों के लाभ के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश तैयार करने में मदद मिलेगी। अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता वाली इस समिति में द वीक के स्थानीय संपादक सच्चिदानंद मूर्ति, स्वतंत्र पत्रकार शेखर अय्यर, न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा, बिजनेस लाइन के शिशिर कुमार सिन्हा, जी न्यूज के विशेष संवाददाता रविंदर कुमार, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, हिंदुस्तान टाइम्स की स्मृति काक रामचंद्रन, टाइम्स नाउ के अमित कुमार, इकोनॉमिक टाइम्स की वसुधा वेणुगोपाल और पत्र सूचना कार्यालय में एडिशनल डीजींचन प्रसाद शामिल हैं।

आत्मनिर्भरता की ओर भारतीय इस्पात उद्योग

– श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह –
केंद्रीय इस्पात मंत्री

शिमला। भारतीय इस्पात उद्योग को आत्मनिर्भर भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए सक्षम बनाना - मैं 'स्पेशलिटी स्टील' के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को इस रूप में देखता हूं। इस योजना को हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। न्यू इंडिया बनाने की दिशा में उनका दूरदर्शी और रणनीतिक दृष्टिकोण, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और इसके आत्मनिर्भर होने पर जोर देता है। जुलाई में केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, यह पहली नीतिगत योजना है, जिसे लागू करने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह योजना इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे दो तरीकों से संस्थानों की मदद की जा सकती है- सटीकता को ध्यान में रखते हुए सोचें और पेश किये गए विकल्पों के आधार पर बेहतर निर्णय लें। इन विकल्पों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इससे दोनों ही पक्ष जीत की स्थिति में होंगे।

इस योजना के तहत 'स्पेशलिटी स्टील' के वृद्धिशील उत्पादन के लिए पात्र कंपनियों को साल-दर-साल आधार पर पांच साल की अवधि तक प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसलिए, सरकार उन्हें उत्पादों में मूल्य-वर्धन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे दोहरा फायदा होगा। उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्य वर्धित उत्पादों की बेहतर कीमत मिलेगी और योजना के तहत प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। इस योजना से एकीकृत इस्पात उत्पादकों के साथ-साथ द्वितीयक इस्पात उत्पादकों और एमएसएमई को भी लाभ होगा। 'स्पेशलिटी स्टील' के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना बनाई गई है। 'स्पेशलिटी स्टील' की वह श्रेणी, जिसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, को उत्पादकों और उपयोगकर्ता उद्योगों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। 'स्पेशलिटी स्टील' उन 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जिन्हें भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात बढ़ाने के लिए चिन्हित किया गया है और जिनके लिए पीएलआई योजनाओ की मंजूरी दी गई है।

प्रोत्साहन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद देने के साथ आयात में कमी लाकर भारत के विकास को गति देना है। इसके अलावा, इस योजना के तहत अपेक्षित अतिरिक्त निवेश से न केवल घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता विकसित होगी (बल्कि आने वाले समय में इस्पात क्षेत्र, वैश्विक चैंपियन भी बन सकता है। पीएलआई योजना उच्च श्रेणी के स्टील उत्पादन में प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अलावा इस योजना से तकनीकी क्षमताओं को प्राप्त करने और एक प्रतिस्पर्धी व तकनीकी रूप से उन्नत इको-सिस्टम बनाने में सहायता मिलेगी। लगभग 40,000 करोड़ रुपये के निवेश से 'स्पेशलिटी स्टील' की घरेलू क्षमता में वृद्धि होगी, आयात में लगभग 30,000 करोड़ रुपये के कमी आयेगी और निर्यात में लगभग 33,000 करोड़ रुपये के वृद्धि होगी। लगभग 25 मिलियन टन की अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता सृजित होगी। अनुमान है कि इस योजना में लगभग 5,25,000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता है, जिनमें से लगभग 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होंगे और शेष अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे।

स्पेशलिटी स्टील क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए चुना गया था, क्योंकि भारतीय इस्पात उद्योग, इस्पात कारोबार के सन्दर्भ में मूल्य श्रृंखला के निचले स्तर पर काम करता है। वित्त वर्ष 2020-21 में, भारत का इस्पात निर्यात 10.7 मिलियन टन था, जिसमें 'स्पेशलिटी स्टील' का हिस्सा 1.8 मिलियन टन था, जबकि आयात 4.7 मिलियन टन रहा, जिसमें 'स्पेशलिटी स्टील' का हिस्सा 2.9 मिलियन टन था। कुल व्यापार के प्रतिशत के रूप में उच्च आयात और कम निर्यात के इस असंतुलन को पीएलआई योजना द्वारा एकदम से विपरीत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 के तहत 2030-31 तक रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिकल स्टील, विशेष स्टील और मिश्र धातुओं की पूरी मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश इस विजन को तभी हासिल कर सकता है, जब सरकार इस तरह के 'स्पेशलिटी स्टील' के उत्पादन को बढ़ाने और मूल्य श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करे।

मुझे विश्वास है कि यह पीएलआई योजना हमें उच्च गुणवत्ता वाले मूल्य वर्धित इस्पात का उत्पादन करने वाले देशों में शामिल करने में मदद करेगी। आइए हम 'मेक इन इंडिया' ब्रांड, जिसका अर्थ प्रतिस्पर्धी कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का निर्माण है, को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करें।

नितिन गडकरी ने आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया

शिमला। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार के राजस्व आधार में सुधार करके आर्थिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने, अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश के निर्माण के लिए अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया की 29वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को बढ़ावा देने वाला बुनियादी ढांचा' विषय पर अपने संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दो दशकों में 16 अरब डॉलर से बढ़कर 149 अरब डॉलर हो गया है और इसके 2025 तक 500 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास की गुंजाइश को और तलाशा जाना चाहिए।

गडकरी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के सपने को पूरा करने में बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में 1,400 अरब डॉलर का निवेश कर रही है और जल्द ही देश में समग्र एवं एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति मास्टर प्लान एनआईपी कार्यक्रम के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा और इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए रसद लागत में कटौती करके भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

मंत्री ने कहा कि भारत में लगभग 60 लाख किलोमीटर का

सड़क नेटवर्क है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क अवसंरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि 70% माल और लगभग 90% यात्री आवाजाही के लिए यातायात सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि न केवल आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से बल्कि इसका इस्तेमाल करने वाले माल और यात्री यातायात के सबसे बड़े हिस्से के लिए भी इस नेटवर्क का रखरखाव और विस्तार महत्वपूर्ण है।

गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई विकास वित्त संस्था डीएफआर स्थापित करने की प्रक्रिया में है। संस्था को 20,000 करोड़ रुपये के पूंजी आधार पर स्थापित किया जा रहा है और तीन वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर एकीकृत अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई संपर्क और सड़क नेटवर्क विकसित कर रही है।

मंत्री ने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और कारों के लिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार बन रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां ईवी बैटरी प्रौद्योगिकियों और रेट्रोफिटिंग उद्योग के लिए हमारे अनुसंधान और विकास के साथ सहयोग कर सकती हैं।

गडकरी ने कहा कि हम गुणवत्ता, लागत प्रभावशीलता और स्थिरता से समझौता किए बिना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। मंत्री ने कहा कि वह हमेशा कहते थे कि अमेरिकी सड़कें इस वजह से अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका समृद्ध है, बल्कि अमेरिका इस वजह से समृद्ध है क्योंकि अमेरिकी सड़कें अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इस देश में समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, लागत प्रभावी और टिकाऊ विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

सौर ऊर्जा उत्पादन पर एयरोसोल और बादलों के प्रभाव से वित्तीय हानि होती है

शिमला। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया है कि हवा में विद्यमान वाष्प और सूक्ष्म ठोस कणों अर्थात एयरोसोल, धूल और बादल भवनों की छतों पर स्थापित फोटोवोल्टिक (फोटोवोल्टिक एंड रूफ टॉप इंस्टालेशंस) सौर ऊर्जा उपकरणों (फोटोवोल्टिक एंड रूफ टॉप सोलर इनर्जी इंस्टालेशंस) से मिलने वाली सौर ऊर्जा के उत्पादन को कम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अच्छी-खासी वित्तीय हानि होती है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि फोटोवोल्टिक और छतों पर स्थापित उपकरणों (रूफटॉप इंस्टॉलेशन) पर कुल एरोसोल प्रकाशिक (ऑप्टिकल) गहराई का प्रभाव 15 लाख 50 हजार रुपये तक की वार्षिक वित्तीय हानि है। धूल और बादलों के कारण इससे संबंधित वित्तीय नुकसान क्रमश: 05 लाख 60 हजार रूपये और 24 लाख 70 हजार रुपये है। यह अनुमान भारतीय सौर ऊर्जा उत्पादकों और बिजली प्रबंधन संस्थाओं को पारेषण और वितरण प्रणाली के कुशल संचालन और ग्रिड स्थिरता में अनुकूलन के लिए मदद कर सकता है।

हाल के वर्षों में भारत जैसे विकासशील देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, और जहां पर्याप्त सौर संसाधन हैं। फोटोवोल्टिक (पीवी) और केन्द्रीयकृत सौर ऊर्जा (सीएसपी) संयंत्र प्रतिष्ठानों में हालांकि, बादल और एयरोसोल द्वारा सौर विकीर्ण को सीमित कर दी जाने के कारण इनके कार्य निष्पादन और क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। सौर प्रणाली को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए उचित योजना के साथ ही सौर क्षमता का अनुमान लगाने की आवश्यकता भी होती है।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीटयूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज-एआरआईईएस), नैनीताल, भारत के शोधकर्ताओं तथा एथेंस की राष्ट्रीय वेधशाला (एनओए), ग्रीस ने विश्लेषण और म डल सिमुलेशन के साथ मध्य हिमालयी क्षेत्र में एक उच्च ऊंचाई वाले दूरस्थ स्थान पर सौर ऊर्जा क्षमता पर एरोसोल और बादलों के प्रभाव का अध्ययन किया।

रिमोट सेंसिंग जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि वार्षिक आधार पर, क्षैतिज सतह या वैश्विक क्षैतिज विकिरण (जीएचआई) पर कुल सौर विकिरण घटना के लिए कुल एरोसोल क्षीणन (एटेनचुएशन) क्रमश: 105 के डब्ल्यूएच एम$^{-2}$ (kWhm^{-2}) और 266 के डब्ल्यूएच एम$^{-2}$ (kWhm^{-2}) था। सूर्य या बीम क्षैतिज विकिरण (बीएचआई) से प्राप्त प्रत्यक्ष सौर विकिरण (क्रमश जीएचआई और बीचआई क्रमश: 245 के डब्ल्यूएच एम$^{-2}$ (kWhm^{-2}) और 271 (kWhm^{-2}) के क्षीणन के साथ संबंधित बादल (क्लाउड) के प्रभाव बहुत अधिक मजबूत होते हैं। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा में इस नुकसान के कारण होने वाले वार्षिक वित्तीय नुकसान की भी गणना की है।

एआईआरआईईएस नैनीताल, भारत के वैज्ञानिक डॉ. उमेश चंद्र दुमका के साथ-साथ नेतृत्व में एनओए, ग्रीस के वैज्ञानिक प्रो. पानागियोटिस जी कोस्मोपोलोस, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए), बंगलुरु, भारत के वैज्ञानिक डॉ. शांतिकुमार एस. निंगोमबम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूडकी, भारत के शोध संकाय की आकृति मासूम की सहायता से किए गए इस शोध से इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन पर एरोसोल और बादलों के प्रभाव की व्यापक जांच आंकड़े मिल रहे हैं। इसके अलावा, यह अध्ययन मध्य हिमालयी क्षेत्र में काल्पनिक रूप से स्थापित किए जाने वाले एक 01 मेगावाट की नाममात्र शक्ति वाले पीवी (फोटोवोल्टिक) और केंद्रित सौर ऊर्जा (सीएसपी) प्रणाली के एक काल्पनिक परिदृश्य का अनुकरण करके वित्तीय हानि के विश्लेषण का भी प्रयास करता है।

वैज्ञानिक अब सौर ऊर्जा उत्पादन के स्तरों और उसके वितरण को भारत भर में चुनी हुई स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में होने वाली खपत के साथ जोड़ने और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा इको सिस्टम के लिए सौर पूर्वानुमान और ऊर्जा के प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार एरोसोल और क्लाउड प्रभावों को मापने की योजना बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर विजय मशाल ग्रहण की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मंडी के सेरी मंच में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर विजय मशाल को ग्रहण किया। विजय मशाल यात्रा के स्वागत के लिए ऐतिहासिक सेरी मंच को

आकर्षक ढंग से सजाया गया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की शानदार विजय की याद दिलाता है, बल्कि यह बांग्लादेश के जन्म की कहानी भी बताता है। उन्होंने कहा कि यह विजय भारतीय सैनिकों के सामरिक कौशल और वीरता का जीता- जागता दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 16 दिसम्बर, 2020 को विजय मशाल जलाकर स्वर्ण विजय वर्ष समारोह आरम्भ किया गया और तब से विजय मशाल देशभर की यात्रा कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को वीरभूमि का गौरव दिलाने में प्रदेश के वीर सपूतों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिमाचल के लगभग 1700 वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जवानों की वीरता इस बात से प्रदर्शित होती है कि राज्य के सपूतों को 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 1111 सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हिमाचल के 261 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में 121944 भूतपूर्व सैनिक, 923 वीर नारियां और 36731 अन्य सैन्य विधवाएं हैं। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हिमाचल के 52 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राज्य को गौरवान्वित किया था। इस युद्ध के दौरान राज्य के सैनिकों ने 2 परमवीर चक्र, 6 वीर चक्र और 12 सेना पदक और एक मेन्शन-इन-डिस्पैच प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1971 के युद्ध शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. अनन्थानारायणन ने मंडी में शहीद स्मारक का दौरा किया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

16वीं राइजिंग स्टार कॉर्पस योल के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. अनन्थानारायणन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध भारत के लिए निर्णायक क्षण था क्योंकि इस युद्ध द्वारा भारत ने पाकिस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देवभूमि है, बल्कि एक वीर भूमि भी है। राज्य के लाखों युवा देश के सशस्त्र बलों में सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोग की वेबसाइट का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार

के बारे में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को जागरूक करने के साथ-साथ उनसे प्रतिक्रिया भी ली जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत और व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को पोषणयुक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए फोर्टिफाइड गेहूं और चावल प्रदान कर रही है।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र सिंह घोंकरोकटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को वेबसाइट की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी।

सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सी. पॉलरासु, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. आर.एन. बत्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक के.सी. चमन, आयोग के सदस्य सचिव अनिल चौहान, अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश ने किए 3,307 करोड़ रुपये के 27 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में राज्य सरकार ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3307 करोड़ रुपये के 27 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए, जिससे प्रदेश के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश अन्य पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से व्यापार में सुगमता में आगे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए हर संभव सुविधाएं, प्रोत्साहन व रियायतें प्रदान कर रही है। राज्य सरकार निवेशकों को किफायती दर पर भूमि, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और सुलभ प्रशासन जैसे विशिष्ट लाभ प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ निवेशक प्रदेश में इथेनोल इकाइयां स्थापित करने में रूचि दिखा रही हैं।

मैसर्ज ट्राइडेंट कम्पनी ने टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन और मैसर्ज बेटर टूमारो इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 490 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।

मैसर्ज माधव एग्रो ने निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये तथा मैसर्ज हिमालयन ग्रुप ऑफ इस्टीटयूट ने प्रदेश में पहले कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। मैसर्ज पिटारा टीवी ने प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। अपोलो हॉस्पिटल की फ्रेंचाइजी मैसर्ज मेटाफिजिकल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने 250 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। मैसर्ज नचिकेता पेपर लिमिटेड ने क्राफ्ट और डुपलेक्स बोर्ड के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। भारत सरकार के मिश्रित ईंधन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में इथेनोल निर्माताओं को आमंत्रित किया है। प्रदेश में इथेनोल उत्पादन के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत के कुल 6 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्राप्त प्रस्तावों का उद्देश्य इथेनोल, चिकित्सा उपकरण, शिक्षा और कौशल विकास, फार्मास्यूटिकल्स, कागज निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि कुछ उद्यमियों ने प्रदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्रों और थीम पार्क विकसित करने में रूचि दिखाई है।

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 के अन्तर्गत पहले से ही निजी औद्योगिक क्षेत्रों और थीम पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन एवं रियायतों का प्रावधान किया है।

निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कोविड की स्थित सामान्य होने की स्थिति में प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए भी प्रयासरत है।

राज्य ने कोविड टीकाकरण की पहली खुराक का लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल किया: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को बधाई दी और लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। प्रधानमंत्री 6 सितंबर को राज्य के कुछ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे, जिन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में अतुलनीय कार्य किया है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से राज्य के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों चिकित्सा अधीक्षकों, उपमंडल अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न स्थानों जैसे जिला, उपमंडल और खण्ड विकास मुख्यालयों के अलावा अन्य प्रमुख स्थानों पर 90 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि लोग इस मेगा इवेंट में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे और इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के संबंध में अपने विचार साझा करेंगे।

जय राम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को टीकाकरण की पहली खुराक से शेष बचे व्यक्तियों के लिए विशेष अभियान आरम्भ करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल, कुल्लू जिले के मलाणा और शिमला जिले के डोडरा क्वार जैसे दुर्गम क्षेत्रों को चिन्हित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि शेष व्यक्ति की पहचान कर टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण तरीके

से अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले कुछ चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं या किसी अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की पहचान करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस स्थल पर कार्यक्रम की स्क्रीनिंग हो उस स्थल पर आम जनता के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन सभाओं में लोगों द्वारा सरकार के दिशा-निर्देशों जैसे फेस मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए स्थानीय विधायक, टीकाकृत व्यक्तियों तथा जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र के शेष बचे व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए राज्य के हेलीकॉप्टर की विशेष उड़ान संचालित की जाएगी।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए अधिकारियों को शेष व्यक्तियों का 4 सितम्बर तक टीकाकरण करवाने के लिए विशेष अभियान आरम्भ करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य ने टीके के शून्य अपव्यय के लक्ष्य को भी बनाए रखा है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

शिमला। समझौता ज्ञापन से 'ए-हेल्प' के माध्यम से पशुधन संसाधित व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का उपयोग सुनिश्चित होगा। डीएएचडी (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) और एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का सहयोग डीएएचडी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगा

आजादी का अमृत महास्तव के भाग के रूप में, अतुल चतुर्वेदी, सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और एन एन सिन्हा, सचिव,ग्रामीण विकास विभाग ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी), एमओएफएएचडी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एमओआरडी के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए एसएचजी मंच का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि भवन में डीएएचडी और एमओआरडी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, गिरिराज सिंह भी उपस्थित हुए।

इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री, डॉ बीएल मुरुगन, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, फग्गन सिंह कुलस्ते और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद थे।

पशुपालन और डेयरी विभाग विभिन्न मध्यवर्तनों और प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक समुदाय के लिए रोजगार एवं उद्यमिता का ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान कर रहा है, जैसे एएचआईडीएफ (पशुपालन अवसंरचना विकास कोष), डीआईडीएफ (डेयरी अवसंरचना विकास कोष), एनएडीसीपी (राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम), एफएमडी (मुंहपका-खुरपका रोग) और ब्रुसेलोसिस आदि।

सरकार द्वारा हाल ही में 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के लिए पूरे देश में पशुपालन और डेयरी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मौजूदा योजनाओं के विभिन्न घटकों में संशोधन और पुनर्संस्करण करने के बाद कई गतिविधियों को शामिल करते हुए एक विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है।

ग्रामीण विकास विभाग भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान करने के लिए इसी प्रकार के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आजीविका गतिविधियों में शामिल हैं और विशेष रूप से वे पशुधन के क्षेत्र में काम कर रही है।

इसलिए, किसानों को सहायता प्रदान करने और पशुधन क्षेत्र के माध्यम से उनकी आय को दोगुना करने वाले सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डीएएचडी और डीओआरडी के प्रयासों में तालमेल और समन्वय स्थापित होना समय की मांग है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, इसके द्वारा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की सेवाओं को पशुधन संसाधन व्यक्तियों और प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में एक नए मान्यता प्राप्त मॉडल के माध्यम से उपयोग करने का भी निर्णय लिया है, जिसका नाम 'ए-हेल्प' (एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टोक

प्रोडक्शन) है।

इस मॉडल को ए-हेल्प वर्कर के रूप में आगे प्रशिक्षण और मान्यता प्रदान करते हुए पशुधन (पशुसखियों के लिए डे-एनआरएलएम के अंतर्गत विकसित किए गए मौजूदा कैडर का उपयोग करके पूरे देश में लागू किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) बैकवर्ड और फॉर्वर्ड दोनों प्रकार के संपर्कों के माध्यम से कृषि आजीविका क्षेत्र को समर्थन प्रदान कर रहा है। बैकवर्ड संपर्कों के अंतर्गत, पाशुसखियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, जिन्हें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के भाग के रूप में संरचित मॉडयूल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और पशु पाठशालाओं के माध्यम से महिला किसानों को सेवाएं प्रदान की जा रही है, साथ ही साथ किसानों को उनके घर तक सेवाएं पहुंचाई जा रही है।इस अभियान में 40,000 से ज्यादा पशुसखियां शामिल हैं। इस अभिसरण के द्वारा इन सामुदायिक संवर्गों के माध्यम से डीएएचडी योजनाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी और यह संवर्गों के लिए अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने में भी मदद करेगा, जिससे उनकी स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला ने इस बात को रेखांकित किया कि डीएएचडी और डीआरडी के प्रयासों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित करना समय की मांग है, विशेष रूप से किसानों को सहायता पहुंचाने और पशुधन क्षेत्र के माध्यम से उनकी आय को दोगुनी करने वाले साझा उद्देश्य के लिए।

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, गिरिराज सिंह ने इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए दोनों विभागों को शुभकामनाएं प्रदान की और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने वाले साझा उद्देश्य और मौजूदा संसाधनों का सबसे प्रभावपूर्ण उपयोग करने की दिशा में दोनों विभागों के बीच प्रभावशाली संयुक्त सहक्रियाशील कार्य होने की कामना की।

वैज्ञानिक प्रतिभाओं और स्टार्ट-अप की पहचान हेतु केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता

शिमला। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर समन्वय के माध्यम से उद्यमियों और स्टार्टअप के साथ-साथ संभावित युवा शोधकर्ताओं और महिला वैज्ञानिकों की पहचान करने तथा जनता तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की भागीदारी के साथ आयोजित एक साल के 'विज्ञान उत्सव' का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसमें राज्यों की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) परिषदों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक बुनियादी निर्धारित आवश्यकता है तथा देश, केंद्र-राज्य के समन्वित प्रयासों से वैज्ञानिक दुनिया में अब एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है।

प्रधानमंत्री के 75वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन का उल्लेख करते हुए कि 'भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव केवल एक समारोह तक सीमित नहीं होना चाहिए', डॉ. सिंह ने कहा कि अब नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की आधारशिला रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा यहां से शुरू होने से लेकर अगले 25 वर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद जब हम भारतीय स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे तब वह एक नए भारत के निर्माण की अमृत अवधि का प्रतीक होगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में अगले 25 वर्षों के लिए कार्य योजना (रोडमैप) वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी प्रौद्योगिकियों के मानचित्रण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राज्यों को सभी क्षेत्रों में अपनी प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का उपयोग करने में मदद मिल सके।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप, ने उल्लेख किया कि यह विज्ञान उत्सव सभी राज्यों के संपूर्ण विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के पारिस्थितिकी तंत्र को आगे लाने के लिए पहचाने गए विषयों के माध्यम से सभी सम्बद्ध हितधारकों के साथ एक बड़ा जुड़ाव स्थापित करने में सक्षम होगा और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास की दिशा में आगे जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में वैज्ञानिक 'जी' और सलाहकार डॉ. देवप्रिया दत्ता ने कहा, 'राज्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के माध्यम से कई राज्यों में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं और इस कार्यक्रम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देगा।' अगस्त 2022 तक यह विज्ञान उत्सव सभी राज्यों की भागीदारी से मनाया जाएगा।

आकांक्षा कुमारी भूमिगत खान में काम करने वाली पहली महिला

शिमला। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आकांक्षा कुमारी को बधाई दी है। वे कोयला मंत्रालय के तहत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की पहली महिला खनन अभियंता हैं। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय मंत्री ने आकांक्षा कुमारी को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के उत्तरी करनपुरा क्षेत्र में चूरी की एक भूमिगत खदान में काम करने वाली पहली महिला खनन इंजीनियर बनने के लिए बधाई दी।

जोशी ने कहा कि आकांक्षा कुमारी की यह उपलब्धि महिलाओं को भूमिगत कोयला खदानों में काम करने की अनुमति देकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा उनके लिए और अधिक अवसर पैदा करने के कार्य में प्रगतिशील शासन का वास्तविक उदाहरण है।

एक खनन स्नातक आकांक्षा कुमारी ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के उत्तरी करनपुरा क्षेत्र में चूरी भूमिगत खान में कार्य करना शुरु कर दिया है। इस प्रक्रिया में, वह सीसीएल में शामिल होने वाली पहली महिला खनन इंजीनियर बनी हैं। महिला कर्मचारी अधिकारी और डॉक्टर से लेकर सुरक्षा गार्ड तक और यहां तक

कि डंपर तथा शॉवेल जैसी भारी मशीन चलाने तक की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं और वे प्रत्येक भूमिका में उत्कृष्ट रही हैं। हालांकि, यह पहला अवसर है जब दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनियों में से एक की मुख्य खनन गतिविधि में इस तरह का प्रगतिशील बदलाव देखने को मिलेगा। उनकी उपलब्धि की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आकांक्षा महारत्न समूह कोल इंडिया लिमिटेड में दूसरी खनन इंजीनियर और भूमिगत कोयला खदान में काम करने वाली पहली महिला हैं। झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव की रहने वाली आकांक्षा ने अपनी स्कूली शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी की है। एक खनन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली आकांक्षा ने कोयला खनन गतिविधियों को काफी करीब से देखा और बचपन से ही उनमें खनन कार्यों के प्रति रुचि थी। इस प्रकार आकांक्षा ने बचपन से ही खानों और इनकी गतिविधियों के प्रति एक स्वभाविक जिज्ञासा विकसित की, जिसके बाद उन्होंने धनबाद के बीआईटी सिंदरी में खनन इंजीनियरिंग का विकल्प चुना।

कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल होने से पहले आकांक्षा ने राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बलरिया खान में तीन साल तक काम किया है। वह अपने सपनों को पूरा करने में दिए गए अथक समर्थन के लिए अपने परिवार को श्रेय देती हैं। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल होना उनके बचपन के सपने को पूरा करने जैसा था और इसके लिए अब उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की उम्मीद है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्राईवेट सैक्टर के स्टोरों में 20% जगह बागवानों के लिये रखने की शर्त पर अमल क्यों नहीं

- सेब क्षेत्रों में ही 65500 मीट्रिक टन क्षमता के स्टोर स्थापित
- प्राईवेट सैक्टर में 28 और सरकारी क्षेत्र में केवल 6 स्टोर
- सरकारी स्टोरों की क्षमता केवल 2980 टन

शिमला/शैल। इस समय पूरे देश में किसान आन्दोलन सबसे प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। बल्कि इस आन्दोलन की गंभीरता का परिणाम माना जा रहा है कुछ राज्यों में उपचुनाव का टाला जाना। संयोगवश इसी आन्दोलन के दौरान हिमाचल में सेब सीज़न आ गया है। हिमाचल में सेब की आर्थिकी पांच हज़ार करोड़ के करीब है। प्रदेश में सेब के व्यापार में कोल्ड स्टोर मालिकों का सबसे बड़ा दखल हो चुका है। इसमें भी अदानी का एग्रो फ्रैश सबसे बड़ा प्लेयर है क्योंकि अदानी के प्रदेश में तीन कोल्ड स्टोर हैं। अन्य लोगों के एक –एक है। यह सभी कोल्ड स्टोर केन्द्र में 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही प्रदेश में बने हैं। जब इन लोगों ने यह स्टोर स्थापित करने के लिये सरकार में आवेदन किये और सरकार ने इन्हें अनुमतियां प्रदान की तब यह शर्त रखी गयी थी कि कि यह लोग अपने स्टोरों में 20% स्थान यहां के बागवानों के लिये सुरक्षित और उपलब्ध रखेंगे। स्वभाविक है कि पांचों स्टोरों में इस क्षेत्र में पैदा हाने वाले फल और सब्जियां ही रखी जानी थी। यह रखने के लिये स्थानीय स्तर पर खरीद किया जाना भी स्वभाविक था। सीज़न शुरू होने पर खरीद करके स्टोरों में भण्डारण करना और सीज़न खत्म होने के बाद इस भण्डारण को बाज़ार में बिक्री के लिये ले जाना स्वभाविक प्रक्रिया के अंग है।

अब नये कृषि कानूनों में आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण और उनके बिक्री मूल्य पर नियन्त्रण हटा लिया गया है। इसी के साथ उत्पादक और व्यापारी की परिभाषाओं में भी बदलाव किया गया है। व्यापार स्थलों की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। अब ए.पी.एम.सी परिसरों के बाहर भी खरीद बेच की जा सकती है और इस पर किसी तरह की कोई फीस नहीं दी जानी है। इस बार इन कोल्ड स्टोरों के मालिकों ने सेब की खरीद के समय उसके भाव गिरा दिये। पिछले साल के मुकाबले रेट में सोलह रूपये की कमी कर दी गयी। इस कमी से हर बागवान प्रभावित हुआ। पिछले वर्ष जो सेब अदानी ने 80रू किलो खरीदा और सीज़न के बाद दो सौ रू बेचा था उसमें इस बार इतनी कमी हो जाने से सेब उत्पादकों का परेशान होना स्वभाविक था। इस परेशानी का परिणाम हुआ बागवानों का आन्दोलित होना। इस आन्दोलन को राकेश टिकैट के आने से और ताकत मिल गयी। लेकिन जब सेब की कीमतों में गिरावट के लिये बागवान लदानी – अदानी के खिलाफ नारे लगा रहे थे तब उसी समय बागवानी मन्त्री बागवानों को खुले में क्रेटों में सेब बेचने की सलाह दे रहे थे। मुख्यमन्त्री तुड़ान रोकने की राय दे रहे थे। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा इस संकट के लिये अदानी को दोष देने की बजाये उसका एक तरह से पक्ष ले रहे थे।

आज प्रदेश में प्राईवेट सैक्टर में 28 कोल्ड स्टोर उपलब्ध हैं। यदि सरकार इन कोल्ड स्टारों में बागवानों के लिये 20% स्थान सुरक्षित और उपलब्ध रखने की शर्त की अनुपालना ईमानदारी से करवा दे तो बहुत हद तक बागवनों की समस्या हल हो जाती है। इस समय जिला शिमला में ही प्राईवेट सैक्टर के 48482 मीट्रिक टन क्षमता के दस स्टोर कार्यरत है। कुल्लु और सोलन में 17018 मीट्रिक टन क्षमता के स्टोर प्राईवेट सैक्टर में है। इनके अतिरिक्त ऊना में 13717.5 टन क्षमता के स्टोर उपलब्ध है। जबकि सरकारी क्षेत्र में 2980 टन क्षमता के केवल छः स्टोर हैं और इनमें भी विश्व बैंक की योजना के सहायोग से अधिकांश में अपग्रेडेशन का काम चला हुआ है। इस समय प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में 65500 मीट्रिक टन क्षमता के स्टोर स्थापित हो चुके हैं। आने वाले समय में इन स्टोरों के मालिकों का पूरी बागवानी पर अपरोक्ष में कब्जा हो जायेगा यह तय है क्योंकि नये कृषि उपज कानूनों में भण्डारण और कीमतों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है।

ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या आने वाले समय में बागवानों का भविष्य सुरक्षित रह पायेगा? क्योंकि तब बाजार को तो यह स्टोर रैगुलेट करेंगे। कीमतों का बढ़ना और कम होना सब इन पर निर्भर हो जायेगा। आज ही विदेशों से आ रहे ड्यूटी फ्री सेब के कारण स्थानीय उत्पादक अपने को असहाय महसूस करने लग गया है जबकि अभी कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे चल रहा है। आन्दोलनरत किसान इन कानूनों की वापसी की मांग कर रहा है। यदि किन्ही कारणों से यह आन्दोलन असफल हो जाता है तब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की स्थिति क्या हो जायेगी। इन सवालों पर विचार करने की आवश्यकता और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाना भी समय की मांग हो जाता है।

यह हैं प्रदेश में स्थापित कोल्ड स्टोर

District wise list of CA & Cold stores Established in Government & Pvt. Sector along with unding agency in the state.

Name of Distt.:- Shimla

Sr. No.	Name of the Firm	Address	Type	Govt./ Pvt.	Capacity (MT) CS	CA
	HPMC	Rohru, Distt. Shimla	CA Store	Govt.	-	700
	HPMC	Oddi, /tehsil Kumarsein, Distt Shimla.	CA Store	Govt.	-	1000
	HPMC	Gumma, Tehsil Kotkhai, Distt. Shimal	CA Store	Govt.	-	640
	HPMC	Jarol Tikkar, Distt. Shimla.	CA Store	Govt.	-	640
	HPMC	Patlikuhal (Kullu)	CA Store	Govt.	-	700
	HPMC	Parwanoo	Cold store	Govt.	3000	
		Sub total (Govt. sector)			3000	**2980**
	M/S Anubhuti Apples	Sainj, Theog, Distt. Shimla.	CA Store	Pvt.	-	3500
2	M/S Him Agri Fresh Ltd.	Balghar, Tehsil Theog, Distt Shimla	CA Store	Pvt.	-	5032
3	M/S JCO Agri Fresh Ltd.	Kachi. Tehsil Theog, Distric Shimla	CA Store	Pvt.	-	1200
4	M/S Adani Agri Fresh Ltd.	Village Rewali Sainj. Tehsil Rampur. Distt. Shimla	CA Store	Pvt.	-	6000
5	M/S Adani Agri Fresh Ltd.	Sainj. Tehsil Theog. Distt. Shimla	CA Store	Pvt.	-	6000
6	M/S Adani Agri Fresh Ltd.	Mehandli. Tehsil Rohru,. Distt. Shimla	CA Store	Pvt.	-	8500
7	M/S Dev Bhumi Cold Chain Pvt Ltd.	Matiana, distt. Shimla	CA Store	Pvt.	-	5250
8	M/S Him Fresh Produce Pvt. Ltd.	Bagori, Gumma, distt. Shimla.	CA Store	Pvt.	-	2500
9	M/S Shivin CA Store	Sima. Tehsil Rohru, Distt. Shimla.	CA Store	Pvt.	-	5500
10	M/S Bija Agri Fresh Ltd.	Bithal, Tehsil Rampur, Distt. Shimla	CA Store	Pvt.	-	5000
		Total (in pvt. Sector)				**48482**
		total(Pvt.Sector)				**13717.5**

Name of Distt.:- Kullu

Sr. No.	Name of the Firm	Address	Type	Govt./ Pvt.	Capacity (MT) CS	CA
1	M/S Trail Blazer Fruit company	Trail Blazer Fruit company VPO Hurla Distt. Kullu HP	CA Store	Govt.	-	500
2	M/S Aeromatrix Pvt. Ltd.	Aeromatrix Pvt. Ltd. Vill. Mahili PO Patlikuhal Distt Kullu HP	CA Store	Govt	-	1500
		total(Pvt.Sector)				**2000**

Name of Distt.:- Solan

1	M/S A.R. Transmission	Sh. Ravi Talwar, village Krishan Pura, P.O. Baddi	CA Store	Govt.	-	1600
2	---	Sh. Dharmender, Village Wakna, Po Waknaghat	CA Store	Govt.	-	18
3	M/S Ramvisht Enterprises	Tipra, PO Surajpur, Baddi	CA Store	Govt.	-	1100
4	M/S RKS Future Foods & Cold Chain Pvt. Ltd.	Jharmajri, PO Barotiwala	CA Store	Govt.	-	5000
5.	M/S AB Refer	Kotla, PO Surajpur, Baddi	CA Store	Govt.	-	5000

Name of Distt.:- Una

1	M/S Him cold store-	Miss Shania d/o Sh. Mohs. Mushtag Vill-Bumblu, PO-Kaloh Tehsil-Ghanari Distt-Una H.P.	CA	Pvt.	-	500
2	Thakur Cold Store and Ice factory	Sh Radhey Shyam Jaswal, VPO-Jadla Keori Tehsil- Ghanari District-Una HP	CA	Pvt.	-	2180
3	M/S Jira Foods CA Store	M/S Jira Foods CA Store- Tahliwal Tehsil-Haroli district Una HP	CA	Pvt.	-	5000
4	M/S Vinayak Foods.	M/S Vinayak Foods-Pandoga, Tehsil-Haroli, District Una HP	CA	Pvt.	-	2000
5	Shiv Sharma Cold Store	Shiv Sharma Cold Store-Vikas Sharma and Gurpyal Singh VPO-Lal Singhi	CA	Pvt.	-	4000
6	Shree Krishna Cold Store	Shree Krishna Cold Store-Rajat Katna Vill-Lower Badhera Tehsil-Haroli	CA	Pvt.	-	10
7	Kisan Cold Store	Kisan Cold Store-Somesh Sharma/Satish Sharma VPO-Una.	CA	Pvt.	-	12.5
8	Gupta Cold Store	Gupta Cold Store-Parveen Kumar S/O Sh. Madan Lan Vill-Lalsinghi PO-Una	CA	Pvt.	-	15
5.	M/S Hortitech Food	Baddi, Solan	CA Store	Govt.	-	1300
7.	M/S Himalayan Cotton yarn Ltd.	Village Banalagi (Kuthar) Tehsil Kasauli	CA Store	Govt.	-	1000
		Total(Pvt.Sector).				**15018**

Name of Distt :- Sirmour

	Himalayan International Ltd. Poanta Sahib	Himalayan International Ltd.	CA Store	Govt.	-	2000
		Total(Pvt.Sector).				**2000**
		Total capacity of CA Stores in pvt. Sector (28Nos.)				**81217.5**
		Total capacity of CA Stores established in public sector (4Nos.)				**2980**
		Total capacity of CA stores established in the State (28+4=32Nos.)				**84197.5**